राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
Ministry of Rural Development, Government of India

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 286

प्रगति

समाचार पत्र

मार्च 2019

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस: वन शिक्षा और स्थायी ग्रामीण समितियां

3 | अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस: वन शिक्षा और स्थायी ग्रामीण समितियां

विषय-सूची

7
एक आदर्श गांव का विचार

10
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के दौरान मासिक धर्म के निपटान और स्वच्छता के बारे में बड़ी चर्चा - प्राथमिक चर्चा के रूप में

11
भारत में खाद्य सुरक्षा

13
भारत में जनसंख्या की गतिशीलता और स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके निहितार्थ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

15
वन संसाधन प्रबंधन के लिए खुला स्रोत जी आई एस टूल्स पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

17
पीएमएजीवाई के तहत ग्राम विकास योजना की तैयारी पर क्षेत्रीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण और एसआईपीआरडी, गुवाहाटी, असम में जीपीडीपी के साथ एकीकरण

18
ग्रामीण विकास के लिए भू-संसूचना अनुप्रयोग पर लाइब्रेरी टॉक

19
जेंडर एकीकरण पर संयुक्त राष्ट्र परियोजना के लिए पूर्व एनआईआरडीपीआर संकाय सदस्य को समूह प्रबंधक के रूप में चुना गया

20
पीएमएजीवाई के तहत ग्राम विकास योजना की तैयारी पर क्षेत्रीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण और मैसूरु में जीपीडीपी के साथ एकीकरण

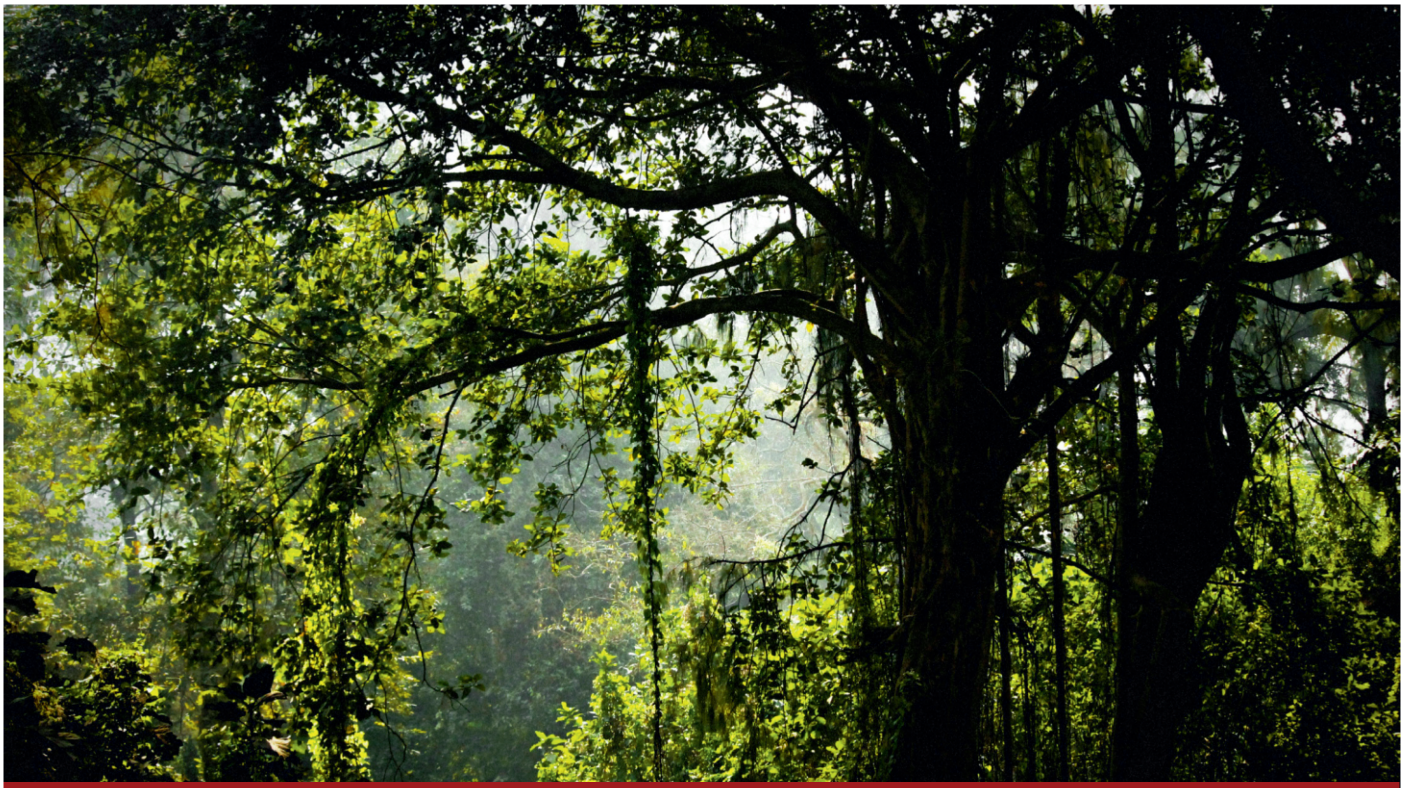

अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस: वन शिक्षा और स्थायी ग्रामीण समितियां

Photo Credits: Anugrah Lohiya from Pixels

जब हम ताजी हवा में सांस लेते हैं और स्वच्छ पानी पीते हैं, तो हम सीधे जंगलों से संबंधित नहीं हो सकते परन्तु हम हरियाली के महत्व और हमारे आसपास की सुंदर प्रकृति को महसूस करते हैं। हमारे जीवन के कई पहलू, जिससे हमरा अस्तित्व प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, घर बनाते या दवाओं का उपयोग करते हैं, एक तरह से जंगलों पर निर्भर करते है। हम अभी तक पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करने और उनके स्थायी उपयोग के माध्यम से भलाई और समृद्धि में योगदान देने वाले वन के महत्व की पूरी तरह से सराहना करते हैं, जिससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां दोनों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। फिर भी, यह सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में जंगलों के महत्वपूर्ण योगदान का सफल प्रमाण फिर से साबित हुआ है। जलवायु परिवर्तन, स्थायी आजीविका का समाधान करना और गरीबी उन्मूलन में से कुछ एसडीजी हैं जहां वन मुख्य भूमिका निभाते हैं। विकासशील दुनिया के अधिकांश लोग अभी भी भोजन, चिकित्सा और आजीविका के रूप में जंगलों से अपने महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त करते हैं।

प्राथमिक स्टेकहोल्डरों अर्थात जंगलों के समीप और जंगल में रहने वाले ग्रामवासियों की सीधी भागीदारी सहित जंगल से प्रेम भाव रखना प्रशंसनीय कार्य होगा।

हालांकि, संरक्षण और बढ़ती मानव आबादी के प्रति उदासीन रवैया, तेजी से शहरीकरण और कृषि के लिए जंगल को काटने से वनों की पूर्ववर्ती हानि खतरनाक रूप से उच्च दर पर देखी गई है। यूएन के सामाजिक और आर्थिक विभाग की एक हालिया रिपोर्ट में, यह दावा किया गया है कि वनों की कटाई के कारण दुनिया भर में हर साल 32 मिलियन एकड़ जंगल समाप्त हो रहे है। यह दुनिया के 80 प्रतिशत स्थलीय जैव विविधता के लिए प्रत्यक्ष खतरे का विस्तार करता है और सबसे बड़ी कार्बन सिंक में से एक में प्रमुख कारक कार्बन के उत्सर्जन के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

भारत में वन

भारत में वन लुप्त होते जा रहे हैं, सक्षम और व्यापक राष्ट्रीय वन नीति (1988) के निपटान के बावजूद, जिसने 33 प्रतिशत वन आकार को बनाए रखने की सिफारिश के साथ पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने में वनों के लिए अपनी सुरक्षात्मक भूमिका पर जोर दिया। मनुष्य और मवेशियों की आबादी में वृद्धि के कारण, कृषि और अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए वन क्षेत्रों की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, रेलवे, रोडवेज, बांधों, परियोजनाओं, पुलों, आदि के रूप में बुनियादी ढाँचे के विकास ने वन आकार में भारी गिरावट को को बढाया है।

भारत ने पिछले 30 वर्षों में बड़े जंगलों को 23,716 औद्योगिक परियोजनाओं (14,000 किमी) और निर्विवादित, लेकिन जंगल की आग में बड़ा क्षेत्र खो दिया है। 0.57 प्रतिशत की वार्षिक वनरोपण दर के बावजूद, प्रति मिनट 2.5 हेक्टेयर वनों की कटाई की उच्च दर के साथ, भारत मरुस्थलीकरण की ओर बढ़ रहा है।

Photo Credits: Y. D. Imran Khan

2017 की वन रिपोर्ट (2018 में प्रकाशित) के अनुसार, भारत के वृक्ष और वन आकार ने 2015 से दो वर्षों में 1 प्रतिशत (8,021 किमी) की वृद्धि दर्ज की है। कुल वन कवर 7,08,273 किमी है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.54 प्रतिशत है। वन और वृक्षकवर संयुक्त 8,02,088 किमी है, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.39 प्रतिशत। वन और वृक्षों की आड़ में 24.4 प्रतिशत भूमि क्षेत्र के साथ भारत दुनिया में 10 वें स्थान पर है, भले ही यह दुनिया के सतह क्षेत्र का 2.4 प्रतिशत है और 17 प्रतिशत मानव और 18 प्रतिशत पशुधन आबादी की जरूरत को पूरा करता है। । नवीनतम खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की रिपोर्ट के अनुसार, वन क्षेत्र में सबसे अधिक वार्षिक शुद्ध लाभ की रिपोर्ट करने वाले शीर्ष दस देशों में भारत को सूची में 8 वें स्थान पर रखा गया है।

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह महसूस किया गया था कि दुनिया वनों के महत्व को आंक कर रही है और वैश्विक नीति निर्माताओं से कम से कम संबंधित है। इसे वर्ष 2011 में अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में उपयोगी योगदान के लिए चिह्नित किया गया था।

वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महा सभा ने अपने 67 वें सत्र में स्थायी प्रबंधन, संरक्षण वर्तमान और भावी पीढ़ियों को लाभ और सभी प्रकार के वनों और पेड़ों के बाहर जंगलों के सतत विकास को मजबूत करने के लिए सभी स्तरों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने माना कि जागरूकता से संबंधित गतिविधियों को मनाने और उनका पीछा करने और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष से परे जंगलों का प्रबंधन करने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त तारीख नहीं है। इसने विभिन्न रिपोर्टों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञानों पर भी ध्यान दिया, मुख्य रूप से 6 से 25 नवंबर 1971 के दौरान संगठन द्वारा आयोजित सम्मेलन के खाद्य और कृषि संगठन का सोलहवां सत्र, जिसने प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस की स्थापना का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, लोगों को वनों के बाहर सभी प्रकार के वनों और पेड़ों से संबंधित गतिविधियों को आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे कि वृक्षारोपण अभियान, वनों की कटाई को रोकने के तरीके अपनाना आदि। यह वनों और उनके महत्व के बारे में अधिक जानने तथा जलवायु परिवर्तन रणनीतियों का मुकाबला करने में वनों की भूमिका को पहचानने के लिए विचारों और विचारों को साझा करना और एक साथ काम करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है।

जंगलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्थायी प्रबंधन के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष विशिष्ट विषय प्रदान करता है। इस वर्ष 2019 के लिए विषय 'वन और शिक्षा' के साथ एक संदेश है, 'वनों से प्यार करना सीखे'। यह सतत वन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण प्राप्त करने में सभी स्तरों पर शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देता है। मुख्य लक्ष्य लोगों को यह समझने के लिए शिक्षित करना है कि स्वस्थ जंगलों से दुनिया भर में लचीले समुदायों और समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं का विकास होता है।

हमारे वनों को बनाए रखने के लिए शिक्षा को एक आवश्यक उपकरण माना जा सकता है। अर्थ सम्मिट (रियो डी जनेरियो, जून, 1992) के एजेंडा 21 ने शिक्षा को पर्यावरण और नैतिक जागरूकता, मूल्य और दृष्टिकोण, कौशल और व्यवहार प्रदान करने के लिए वाहक के रूप में माना जो सतत विकास के लिए आवश्यक हैं। इसलिए, एजेंडा 21 को संबोधित करने के लिए वन और शिक्षा एक उपयुक्त विषय है, जो सतत विकास की दिशा में एक कार्य योजना है। 2030 तक एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका संदेह से परे है । जबकि एस डी जी 15 वनों के स्थायी रखरखाव को प्रोत्साहित करने वाले वनों के लिए विशिष्ट है और वनों की कटाई को कम करने और जैव विविधता के नुकसान को कम करने को,

बढ़ावा देने के लिए, हमारा वन स्वास्थ्य यह तय करने जा रहा है कि हम किसी अन्य लक्षों जैसे गरीबी, भूख ना होना, अच्छा स्वास्थ्य, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई और पारिस्थितिक संतुलन को कैसे प्राप्त किया जाए ? हाल के वर्षों में, दुनिया भर में लगातार प्रयासों के कारण वनों की कटाई की प्रक्रिया धीमी हो गई है । इस दृष्टि से, 'अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस' एसडीजी की आवश्यकता को पूरा करने के साथ-साथ वनों और उनके संरक्षण के बारे में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम' है ।

वन और शिक्षा: भारतीय ग्रामीण संदर्भ

6 वें अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के लिए 'वन और शिक्षा' के संबंध में एफएओ के प्रमुख संदेश, जिसे भारतीय ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से भी जोड़ा जा सकता है;

हमारे वनों को समझना और उन्हें स्वस्थ रखना हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है:

वन पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े ग्रामीण और पारंपरिक समाजों को वन महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करते हैं । जंगलों में और उसके आसपास स्थित लगभग 1.73 लाख गाँवों के साथ, भारत में एक पर्याप्त ग्रामीण आबादी रहती है जो अपनी आजीविका के साथ जंगल से घनिष्ठ रूप से अपने संसाधनों (एमओईएफ, 2006) से जुड़ी है । वनों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करते हुए, स्थायी ग्रामीण समाज को विकसित करना चुनौती है ।

पेड़ों के बारे में सीखना शुरू करने के लिए आप युवा नहीं हैं:

बच्चों को कम उम्र से वृक्षों और वनों से जुड ने की शिक्षा देना जो भविष्य की पीढ़ियों का निर्माण करता है और लाभों और उन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक होते हैं । ग्रामीण बच्चे अच्छी तरह से प्रकृति से जुड़े हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में स्थानीय जैव विविधता और इसके महत्व के बारे में बात करने की आवश्यकता है ।

वनों को स्वस्थ रखने के लिए आधुनिक और पारंपरिक ज्ञान दोनों महत्वपूर्ण हैं:

ग्राम पंचायत स्तर पर पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करना और बनाए रखना, जिसका प्रावधान भारत में पहले से ही जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के माध्यम से है । पीबीआर जैविक और वन संसाधनों से जुड़े पारंपरिक और स्थानीय ज्ञान प्रथाओं का भी दस्तावेज है । ग्रामीण और स्वदेशी समुदायों के पास वन संसाधनों की निरंतर फसल के लिए महत्वपूर्ण अनुभव और ज्ञान है, जिससे जंगल की सुरक्षा सुनिश्चित होती है ।

वानिकी शिक्षा में निवेश बेहतरी के लिए दुनिया को बदल सकता है:

ग्रामीण विकास के लिए प्रमुख कार्यक्रमों जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनईआरजीएस) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के माध्यम से अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सभी हितधारकों द्वारा वानिकी शिक्षा पर पर्याप्त निवेश - वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट वनों की कटाई को कम करेगा और निम्नीकृत मिट्टी को यथावत रखेगा। इस तरह के स्वस्थ और बहाल जंगल हमें पहले बताए गए सतत विकास लक्ष्यों को महसूस करने के लिए लाभान्वित करेंगे। उदाहरण के लिए, ग्रामीण समुदायों और जैव विविधता का संरक्षण के लिए स्थायी आजीविका ।

वन शिक्षा के लिए महिलाओं और पुरुषों की समान पहुंच होनी चाहिए: कई विकासशील देशों की तरह, भारत में ग्रामीण महिलाएं प्राकृतिक संसाधनों और वनों से निकटता से जुड़ी हुई हैं । वनों के आसपास के गांवों की महिलाएं पारंपरिक रूप से वन संसाधनों का प्रबंधन करती रही हैं । वन शिक्षा और क्षमता निर्माण में समान पहुंच और भागीदारी देने से ग्रामीण महिलाओं को वनों और जैव विविधता के स्थायी प्रबंधन के लिए सशक्त बनाया जाएगा।

भारतीय ग्रामीण संदर्भ में, राष्ट्रीय वन नीति (1988) के लागू होने पर वन संरक्षण में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, जहाँ जंगलों के स्थायी प्रबंधन में भागीदार के रूप में वनों के भीतर रहने वाले पारंपरिक और ग्रामीण समाज शामिल थे। यह समावेशी संरक्षण मॉडल से वाणिज्यिक लाभ के दृष्टिकोण मे रूपांतरण था । इसके बाद, 1996 के पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार) अधिनियम 2006 जैसे कानून भी जंगल पर उनके कार्यकाल के अधिकार के लिए आदिवासी और वन गांवों को मान्यता देने और गारंटी देने के लिए हालांकि समय-समय पर सफलता के साथ लगू किये गए थे ।

वन और स्थायी ग्रामीण समितियां

ग्रामीण समितियों और वन, ग्राम भूमि और उनके जैविक संसाधनों के स्थानीय प्रशासन की भागीदारी को मजबूत करने के लिए, जैविक विविधता के संरक्षण के लिए भारत के जैविक विविधता (बीडी) अधिनियम, 2002 की परिकल्पना की गई थी। यह पारंपरिक जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को समान रूप से साझा करने के लिए तंत्र प्रदान करता है । अधिनियम को जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (सीबीडी) के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए लागू किया गया था, जिसके लिए भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, जो पहले बताए गए एजेंडा 21 का एक परिणाम है ।

इसने प्रत्येक ग्राम पंचायत के तहत जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था के तहत गांवों को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त किया । बीएमसी ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वन विभागों से संबंधित कई प्रमुख कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं को शामिल करते हुए, अभिसरण पद्धति के माध्यम से संरक्षण और लाभ के बंटवारे से संबंधित गतिविधियाँ कर सकती है । बीडी अधिनियम और वन के संरक्षण में प्रावधान जैविक संसाधनों को ग्राम पंचायतों की योजना प्रक्रिया में लाया जा सकता है ।

एमजीएनआरईजीएस शुरू करने के लिए एक अच्छा बिंदु हो सकता है, क्योंकि इसमें पहले से ही अभिसरण के लिए दिशानिर्देश हैं । इसके अलावा, एमजीएनआरईजीएस के तहत बजट का

Photo Credits: Y. D. Imran Khan

60 प्रतिशत से अधिक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाता है । हालांकि, बीडी अधिनियम के उद्देश्यों को सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ना और इसे ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) से जोड़ना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है । यह जैव विविधता और जंगलों के संरक्षण के लिए गांवों द्वारा नियोजित गतिविधियों को बढ़ावा देगा। ऐसे कार्यों की परिकल्पना के लिए विभिन्न हितधारकों के स्तर पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आवश्यक है ।

रणनीति के रूप में एक और चुनौतीपूर्ण कार्य गाँव / ग्राम पंचायत स्तर पर कार्बन ऑडिटिंग का विचार हो सकता है । जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, महासागरों के बाद कार्बन के लिए वन दूसरे सबसे बड़े सिंक हैं । स्थायी वन पद्धति अन्य पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं जैसे कि बेहतर मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए, वनों की कार्बन को बढ़ाने के लिए जंगलों की क्षमता बढ़ा सकती है । कार्बन ऑडिट, जिसे आमतौर पर 'कार्बन फुटप्रिंट' के रूप में संदर्भित किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की अनन्य कुल मात्रा का एक उपाय है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक गतिविधि के कारण होता है या परिभाषित सीमा के भीतर किसी उत्पाद, प्रक्रिया या प्रणाली के जीवन चरणों में एक अच्छी तरह से जमा होता है ।

भारत ने 2005 से 2030 तक 33 से 35 प्रतिशत आर्थिक उत्पादन या सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए प्रतिबद्धता जताया है और 2.5 से 3 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाएगा 2030 तक अतिरिक्त वन और पेड़ के आवरण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। इसके अलावा, कार्बन सिंक को बढ़ाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, इसने ग्रीन इंडिया मिशन और वनीकरण के अन्य कार्यक्रमों को लागू करने की योजना बनाई है । इसलिए, भारत ने खुद को जलवायु कार्रवाई पर एक मजबूत नेता होने का संकल्प लिया है । जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में ऐतिहासिक रूप से टॉप-डाउन 'लक्ष्य निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित किया है जिसने राष्ट्रीय कार्रवाई को गति दी है । हालाँकि, जलवायु परिवर्तन में कमी के लक्ष्य (सीओपी 21) और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए, ग्राम स्तर की पहल से जुड़े एक से अधिक ध्यान केंद्रित बॉटम-अप 'दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है ।

ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र जैसे निम्न कार्बन समाज एक स्थायी भविष्य के लिए अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण के बीच संतुलन हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । इसे महसूस करते हुए, गाँव / पंचायत स्तर की योजना में एक कार्बन रणनीति की आवश्यकता होती है और कार्बन ऑडिट कार्बन रणनीति विकसित करने में पहला कदम हो सकता है । शुरू करने के लिए, इसमें कुछ व्यावहारिक कदम शामिल हो सकते हैं जो गाँव / पंचायत कृषि प्रथाओं के साथ-साथ भरोसेमंद खाद्य आपूर्ति और आजीविका को सुरक्षित करने के लिए अपना सकते हैं । इसके अतिरिक्त, यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी या कार्बन सीवेज के बढ़ते समय हासिल किया जा सकता है, जिससे भविष्य में जलवायु परिवर्तन में कमी आ सकती है ।

भावी कार्य

शिक्षा और क्षमता निर्माण के माध्यम से ग्रामीणों (प्राथमिक हितधारकों) को सशक्त बनाना वनों के स्थायी प्रबंधन में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ाएगा । उसे स्थानीय स्वशासन के माध्यम से योजना प्रक्रिया में वन और वन संसाधनों के संरक्षण की नीतियों को रणनीतिक बनाने की आवश्यकता है । वर्तमान जीपीडीपी को वनों के संरक्षण, वनों के बाहर पेड़ों और सामान्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए बढ़ाया जाना चाहिए । अभिसरण और लोगों की योजना के दृष्टिकोण का उपयोग करना जंगलों और इसकी जैविक विविधता के संरक्षण के लिए ग्रामीण समाजों को सशक्त बनाने के लिए एक अभिनव तरीका हो सकता है । नई राष्ट्रीय वन नीति (ड्राफ्ट एनएफपी 2018) जो आकार ले रही है, उपर्युक्त दृष्टिकोण और रणनीतियों को संबोधित करने की आवश्यकता है, जहां सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिए जाने की संभावना है । जंगलों को लगातार प्रबंधित करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संशोधित एनएफपी द्वारा स्थानीय प्रशासन और पंचायतों की भूमिका को पहचानने का भी यह उपयुक्त समय है ।

डॉ. रवींद्र एस. गवली
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएनआरएम
एनआईआरडीपीआर
कवरपेज डिजाइन: श्री वी. जी. भट्ट

आदर्श गांव का विचार

भारत में मॉडल गांवों का उल्लेख करते हुए, एसएजीवाई (सांसद आदर्श ग्राम योजना) दिशानिर्देशों में शामिल - गुजरात के साबरकांठा जिले में पुंसारी ग्राम पंचायत को एक अनुकरणीय रूप में संबोधित किया जा रहा है। एक मॉडल गांव का विचार बहुत ही उल्लेखनीय है या एक रचना है। इसलिए, एक आदर्श गाँव का विचार, और अन्वेषण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मेथोडोलॉजिकल कैनवस, और स्पष्टीकरण देने में सक्षम होने की रूचि पर है। इस अनुभवजन्य सत्यापन ने समझने और समझाने का प्रयास किया; पुंसरी के बारे में क्या खास है कि यह भारत में मॉडल गांवों के लिए एक संदर्भ बिंदु बन गया है?

परिचय

मॉडल गांव का विचार पुराना है, जबकि मॉडल गांव बनाने वाले तत्वों का सवाल अभी भी नया और हैरान करने वाला है। यह नया है क्योंकि विकास मानव समाज के विभिन्न पहलुओं में निरंतर परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में हमेशा एक परिणाम से दूसरे तक जारी रहने की प्रवृत्ति होती है, जिसमें अतिव्यापी तरीके से तत्वों की बहुलता शामिल होती है। इसलिए, एक मॉडल गांव को समझना और समझाना हमेशा जटिल होता है।

'एक मॉडल गाँव' को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पैमाना, अन्य कारकों के आधार पर अलग-अलग होना चाहिए जो गाँव के आकार जैसे खेल में आते हैं; सामुदायिक संरचना; स्थान विशिष्ट लाभ और नुकसान; बाहरी उत्पीड़न की उपस्थिति या अनुपस्थिति आदि, निहितार्थ एक सार्वभौमिक पैमाना है और किसी दिए गए गाँव के विकास को मापना, कुछ विलुप्त होने वाली बाहय भिन्नताओं की त्रुटि के कारण भ्रमित हो सकता है, जैसे कि ऊपर वर्णित हैं - विशेष परियोजना सहायता के माध्यम से महत्वपूर्ण रूप से, बाहरी उत्पीड़न; समाजशास्त्रीय शक्तियां और स्थान-विशिष्ट लाभ और नुकसान एक गांव के अनुभव। इसका मतलब यह है कि एक निर्दिष्ट गाँव यदि यह लगभग दूसरों के लिए एक मॉडल बनने के चरण तक पहुँच गया है या कुछ संकेतक कम हो जाता है तो कुछ माप केवल कुछ परिसीमन के साथ व्यक्त किए जा सकते हैं, और इसे व्यापक रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

मॉडल गांव के बारे में सबसे आसान बात, शायद, एक के बारे में सपने देखना है। एक कागज पर भी एक आदर्श गाँव बनाने की कोशिश की अत्यधिक माँग है। कई अलग-अलग दरवाजों से मुद्दे सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, कोई पूछ सकता है कि बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं ठीक हैं या नहीं; कैसे खेत और गैर-कृषि से संबंधित घटनाओं के बारे में; ग्रामीण रोजगार सृजन और आजीविका विविधीकरण के बारे में कैसे; कैसे ग्रामीण कला और शिल्प और इतने पर और आगे के बारे में।

गुजरात के साबरकांठा जिले में पुंसरी ग्राम पंचायत (जीपी) को अनुकरण के लिए एक मॉडल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस जीपी को संसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) (एमओआरडी, 2014) के दिशानिर्देशों में संदर्भित किया गया है। समझने और समझाने के लिए: क्या लोग पुंसरी को एक आदर्श गांव कहते हैं, किसी को स्पष्टीकरण पर परिप्रेक्ष्य का पता लगाने की आवश्यकता है। एक 'मॉडल गांव' के विचार के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने के लिए परिप्रेक्ष्य की मांग करना। इस अनुभवजन्य अध्ययन के दौरान, और मॉडल गांवों के बारे में कुछ गलत धारणाओं को सुधारने के लिए, पुंसरी में बने रहने वाले स्पॉट-

साल बेहतर और तेज होते जा रहे हैं । दुनिया के सबसे अच्छे दिमाग इंडेक्स बनाने और मानव विकास को मापने पर काम कर रहे हैं । हम अभी तक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं, कि यहां सूचकांक का पूरी तरह से सही सेट है जो विकास को निर्दोष रूप से मापता है । पिछले 25 वर्षों में, हमने मजबूत उपकरण विकसित किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जिसे 'पूरी तरह से सही' के रूप में दावा किया जा सके। न्यूनतम आवश्यक परिप्रेक्ष्य को पकड़ना और आवश्यक समझने और समझाने के लिए एक ढांचा 'निर्धारित करना है ।

जो भी दिशा से, आप पुंसरी जीपी के सरपंच को एक प्रश्न देते हैं, जो इस जीपी को देश में पंचायत के बारे में '' के रूप में '' विकसित करने के पीछे लिंचपिन रहा है, उसका स्टैंड है: ग्रामीण सामाजिक बुनियादी ढाँचे को लगातार बढ़ाने से ग्रामीण लोगों का जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा । इसलिए, पुंसरी मॉडल ग्राम पंचायत के इस अध्ययन ने मुख्य रूप से 'ग्रामीण सामाजिक बुनियादी ढाँचे' का परिप्रेक्ष्य लिया । अगले प्रश्न में उत्तर देने की जरूरत है कि पुंसरी ने ग्राम पंचायत के बारे में इतना विशेष और व्यापक रूप से क्या कहा है और ग्रामीण विकास अभ्यास के लिए क्या पेशकश की है?

आइए हम एक सादृश्य के लिए माइक्रो क्रेडिट और ग्रुप लेंडिंग 'का विचार लें। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम 'का सार या केंद्रीय विचार यह है कि यदि आप घरों में निर्बाध धन प्रवाह के लिए एक तंत्र बनाकर घरेलू अर्थशास्त्र का ध्यान रखते हैं, तो ग्रामीण आर्थिक विकास अपने आप हो जाएगा। इस अवधारणा को सफल बनाने के लिए यह विचार अलग-अलग गांवों, क्षेत्रों और महाद्वीपों (2008, मुहम्मद) में सामुदायिक मानसिकता और क्षमताओं के अनुरूप कई अलग-अलग प्रासंगिक संशोधनों के साथ उपयोग करने के लिए विचार किया गया है । यह दुनिया भर में प्रचालित ब्लूप्रिंट नहीं था; इसके बजाय यह मूल सिद्धांत और अंडरकरंट है जो परिचालन तंत्र को मजबूत बनाता है; और माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम पूरी दुनिया में एक सार्थक सफलता है ।

इसी तरह, पुंसारी मॉडल का केंद्रीय विचार (निचली-रेखा) क्या है? सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल प्रदान करने जैसी बुनियादी ग्रामीण सामाजिक बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दें; बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं; बच्चों की स्कूली शिक्षा; नियमित सड़क की सफाई की व्यवस्था; प्रत्येक घर के लिए

रिफ्लेक्शन की आवश्यकता है ।
य़े हैं:

गलतफहमी - 1:
एक आदर्श गाँव का तात्कालिक परिप्रेक्ष्य गांव हर तरह से एक गाँव पूर्ण है ।

उदाहरण के लिए, एसएजीवाई दिशानिर्देश एक मजबूत रूप से संपूर्ण रूपरेखा प्रदान करता है, जो हर तरह से, सैद्धांतिक रूप से भी पूर्ण माना जा सकता है । यह विचारों से आकर्षित करने के लिए एक व्यापक ढांचा है । हालाँकि, यह कोई खाका नहीं है 'कि इसमें वर्णित प्रत्येक तत्व को धरातल पर उतारने की कोशिश की जाएगी। एक मॉडल गांव के एक अध्ययन में, जैसा कि अध्ययन सामने आया है, किसी को यह पहचानने के लिए मिलता है कि विकास के कई पहलू या स्तर हैं । ये चरण क्रमिक, प्रगतिशील और अक्सर अतिव्यापी होते हैं । वे प्रवेश-प्रतिबंधित डिब्बों की तरह नहीं हैं कि कैसे ग्रामीण विकास एक विषय में निपटने के लिए प्रत्येक विभाग के लिए कॉलेज के पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से कवर किया है । यह कुछ आवश्यकताओं के साथ कोई खाका नहीं है, जिन्हें भरने के लिए एक गांव को 'मॉडल' बनने के लिए अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता है । किसी भी 'विकसित गांव' में, सभी खातों में, कुछ तत्व मौजूद हो सकते हैं और कुछ तत्व विशिष्ट रूप से अनुपस्थित हो सकते हैं । मुद्दा यह है कि एक मॉडल गांव विकास के सभी क्षेत्रों में पूरा नहीं हो सकता है जो कोई भी जमीन पर देखना चाहता है । हमें अपने ढांचे को परिसीमित करने के लिए उचित समझदारी की आवश्यकता है ।

गलतफहमी - 2:
यहां एक अंतिम गंतव्य है जो मॉडल गाँव 'कहलाने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एकदम सही है (या गाँव के विकास की चोटी को छूना चाहिए)।

ऐसा कोई चरण नहीं है जिसे 'विकास का शिखर' कहा जाता है, जिसकी परिभाषा एक गाँव तक पहुँचने वाले अंतिम गंतव्य का वर्णन करती है, इसलिए 'आदर्श गाँव' कहलाने के लिए योग्य होना चाहिए । कोई यह नहीं कह सकता है कि विकास व्यवसायी और पेशेवर गाँवों को 'अंत में सही गंतव्य' की ओर निर्देशित कर रहे हैं । यह किसी भी व्यापक लिस्टिंग की तरह हो सकता है जैसे इसे एसएजीवाई दिशानिर्देशों में दिया गया है, या मानव विकास सूचकांक के तहत दिए गए मानदंड, यह हमेशा पूर्णता के लिए एक संभावना के साथ सापेक्ष और प्रगतिशील है । यह एक फिनिशलाइन की ओर नहीं है । इसलिए, एक पैमाने पर, एक गांव को विकसित के रूप में संबोधित किया जा सकता है, और दूसरे द्वारा इसे अभाव के रूप में मापा जा सकता है ।

यह न केवल पुंसरी ग्राम पंचायत को समझने और समझाने की कोशिश में इस लेखक के अनुभव पर आधारित है, बल्कि मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) पर आधारित राष्ट्रों को मापने में भी वास्तविकता है । एचडी लगातार विकसित हो रहा है, और इंडेक्स लगातार 1990 के बाद से साल-दर-

शौचालय, जिसका अर्थ है कि पंचायत 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की ग्यारहवीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी को ग्राम पंचायत से मांग करती है। इस प्रदर्शन के माध्यम से, पंचायत ने एक नियमित रूप से ग्राम पंचायत के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। दूसरे, अगले स्तर की सुविधाएं जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी (वाई-फाई), सार्वजनिक पता प्रणाली, स्कूलों और राशन की दुकान जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे, एसबीआई ग्राहक सेवा प्वाइंट और एटीएम के माध्यम से बैंक समय से परे बैंकिंग प्रदान करना। गाँव स्तर ने, पुंसरी को राज्य में और देश में भी 'बोली जाने वाली' ग्राम पंचायत बना दिया है। समुदाय की संतुष्टि के भारित औसत ने भी 5-पॉइंट के पैमाने पर 4 से अधिक स्कोर दिखाए हैं जो दर्शाता है कि लोग पंचायत में उपलब्ध संपूर्ण सुविधाओं के बारे में 'पूरी तरह से संतुष्ट' हैं।

धीरे-धीरे काम करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को लगातार बढ़ाने के लिए विकास को सक्षम करने का मतलब है कि धीरे-धीरे काम करना, जो पुंसारी में किया गया है। इसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लगातार विस्तार के माध्यम से चालित प्रभाव को संचालित करने के साथ बुनियादी जरूरतों के सिद्धांत के मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है। निर्मित बुनियादी ढाँचे का स्थायी कामकाज, जीपी द्वारा प्रबंधन ', एवं एसएचजी द्वारा प्रबंधन', और, निजी क्षेत्र के माध्यम से प्रबंधन '/ सरकारी क्षेत्र की भागीदारी' आदि के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।

समझ और स्पष्टीकरण

एक मॉडल गांव को समझने की कोशिश में, पहली चीज जो हमें स्पष्ट होनी चाहिए कि एक मॉडल गांव का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मन का एक ढांचा है / एक मानसिक स्थिति है - या एक बना हुआ परिप्रेक्ष्य / बुद्धि है। लंबे समय तक व्यस्तता के बाद कुछ गाँव एक निश्चित सीमा रेखा के निर्माण के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं, जो एक मॉडल गाँव की 'निश्चित' बन जाती है। हम मॉडल गांवों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ (ओएएन, ई 2002) को छोड़ देते हैं। प्रत्येक मॉडल गाँव से हम एक मॉडल गाँव को टाइप करने वाले 'घटकों' को बनाने में सक्षम हो सकते हैं। एक हॉलमार्क या अनवीयरिंग विज़न नहीं हो सकता है जिसे हम मॉडल विलेज के रूप में लेबल कर सकते हैं। तुलना करने के लिए सोने का कोई मानक नहीं है। हालाँकि, हम विशेषताओं को पहचान सकते हैं; उन प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण करें, जो कुछ विशेषताओं को जन्म देती हैं, जैसे कि एक गुच्छा से गाँव को बाहर निकाल देती हैं।

एक मॉडल गांव, द्वारा एक मनगढ़ंत स्थिति प्रदान करता है जो प्रतिरूप हो सकता है या नहीं; या इसे एक विकास संस्करण के रूप में देखा जा सकता है जो कि उदाहरण के लिए है। एक संस्करण जिसमें कई महत्वपूर्ण विकासात्मक भाग्य शामिल हैं और स्केलिंग के लिए खुद को सरल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, वह बांग्लादेश के माइक्रो क्रेडिट मॉडल की तरह मांगा जाता है।

प्रत्येक गाँव अलग है। यदि हम ब्लैंकेट-प्रकार के घटक प्रदान करने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने स्पष्टीकरण में आसन्न होने जा रहे हैं, जो एक मॉडल गांव बनाने में जाते हैं। हम कुछ मौजूदा मॉडल गांवों से सबक ले सकते हैं - न केवल पुंसारी के, बल्कि दूसरों के भी। यह पद्धतिगत नहीं होगा - बल्कि पौराणिक है - अगर हम पुंसरी को एक गैर-समानांतर उदाहरण के रूप में दोहराने की कोशिश करते हैं, तो उस सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ को संज्ञान में नहीं लेना, जिसमें उसने काम किया है - जिसमें स्थानीय नेतृत्व और आधिकारिक समर्थन शामिल है। मापन को एक वैचारिक ढांचे के भीतर, या उस तर्क के परिप्रेक्ष्य में मजबूत होने का दावा किया जा सकता है। बिंदु पुंसरी ने एक निश्चित सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ में काम किया है, जो शायद एक जैसा नहीं है। एक ही नस में रॉबर्ट चेम्बर्स (1997: 84) लिखते हैं कि महाराष्ट्र में एक गाँव, रालेगाँव सिद्धी को दशकों तक टिकाऊ पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक मॉडल के रूप में बार-बार उद्धृत किया गया है, हालाँकि खाते इस बात से सहमत हैं कि इसमें सबसे असाधारण और असामान्य नेतृत्व है।

एक मॉडल गांव का अध्ययन बहुत रोचक और प्रासंगिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। लेकिन इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है कि कैसे इस तरह के अध्ययन प्रचार के उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि उनका खुद का मॉडल राजनीतिक और वैचारिक टकराव के माहौल में सबसे बेहतर है। कई शोधकर्ताओं ने अपने स्वयं के मॉडल को यथासंभव चमकीले रंगों में पेंट करने के लिए बहुत मेहनत की है - जैसे कि सब कुछ केवल एक ही स्थान पर सिमट गया है और कई उदाहरणों में विकास शोधकर्ताओं और विकास चिकित्सकों ने अन्य प्रणालियों के साथ अपने स्वयं के आदर्श रूप से कार्य करने वाले मॉडल की तुलना करने का खेल खेला, क्योंकि वे एक कम परिपूर्ण वास्तविकता (सुंदर, 1995) में कार्य करते हैं, जो व्यक्तिपरक मूल्य निर्णयों या प्रचार संबंधी बयानों में गिरावट करता है। इसलिए, मॉडल गांवों का अध्ययन करने और उनका अनुकरण करने के लिए, किसी को जानबूझकर या अनजाने में कम किए गए, आदि की झूठी तुलना और भिन्नताओ से सावधान रहना होगा।

निष्कर्ष

शायद, जो समझदारी है, हम उन विशेषताओं को कम कर सकते हैं जो पुंसरी को एक वांछनीय पैटर्न और कुछ सिद्धांतों और मूल्यों के घटक के रूप में पेश करना है, जिन्हें पुंसरी ने विकास के पुंसारी संस्करण बनाने की प्रक्रिया के दौरान अनिवार्य / गैर-परक्राम्य माना। हम दावा कर सकते हैं कि हम पुंसारी ग्राम पंचायत में अपने स्वयं के प्रयोगों से इन सिद्धांतों और मूल्यों पर पहुंचे हैं। सभी ने कहा और किया, हमें समुदाय के साथ एक भागीदारी योजना के लिए जाना पड़ सकता है जहाँ हम एक हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव रखते हैं, या किसी मॉडल गांव की सिफारिश करने के बजाय उन सिद्धांतों और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए जो पुंसारी ग्राम पंचायत के परिवर्तन की सुविधा देते हैं, उस मॉडल को ब्लू प्रिंट के रूप में अपनाया जाएगा। शायद, यह एक बुद्धिमान प्रस्ताव के रूप में लगता है।

डॉ. आर. रमेश
एसोसिएट प्रोफेसर, सीआरआई
एनआईआरडीपीआर

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के दौरान मासिक धर्म के निपटान और स्वच्छता के बारे में बड़ी चर्चा-प्राथमिक चर्चा के रूप में

डॉ. डब्ल्युआर रेड्डी, आईएएस महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और डॉ. एन. वी. माधुरी, एसोसिएट प्रोफेसर, सीजीएसडी के साथ छात्राओं ने संस्थान में महिला दिवस समारोह में भाग लिया

जेंडर अध्ययन एंड विकास केन्द्र द्वारा 8 मार्च 2019 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। जीवन के सभी क्षेत्रों में जेंडर अंतर को समाप्त करने के लिए, एनआईआरडीपीआर सभी जेंडरों के लिए समान अवसर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए दृढ़ता से जोर देता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मासिक धर्म स्वास्थ्य और किशोर और युवा महिलाओं की स्वच्छता के लिए समर्पित किया गया।

इस अवसर पर, एनआईआरडीपीआर ने भारत डॉयनामिक लिमिटेड, हैदराबाद के सहयोग से स्कूली लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए एक सीएसआर परियोजना शुरू की। यह कार्यक्रम 05 फरवरी, 2019 को हस्ताक्षरित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत एनआईआरडीपीआर और बीडीएल (भारत डॉयनामिक लिमिटेड) के बीच एक समझौता ज्ञापन था। बीडीएल ने नेतृत्व किया।

श्री एस. पीरामनयागम, निदेशक (फाइनेंस), और श्री एस. नारायणन, महाप्रबंधक इस कार्यक्रम में भी उपस्थित थे। के. सत्यनारायण रेड्डी, जिला शिक्षा अधिकारी, रंगा रेड्डी जिला कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पड़ोसी सरकारी स्कूलों के 200 किशोर छात्रों को आमंत्रित किया गया था।

अकादमी पुरस्कार प्राप्त रेका ज़ेताबैकी द्वारा लघु निर्देशन "पीरियड्स एंड ऑफ़ सेंटेंस को दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया था। फिल्म की स्क्रीनिंग तीन प्रतिष्ठित पैनलिस्टों द्वारा मासिक धर्म स्वास्थ्य पर एक पैनल चर्चा के बाद की गई थी।

डॉ. अनीता रेगो, लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, हैदराबाद, प्रो. वाई. राम पद्म, भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान और श्रीमती से अनुभवी जनसांख्यिकी तेलंगाना वेलस्पन ग्रुप के कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी विभाग के प्रमुख के. सुरेखा रेड्डी, एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी ने इस अवसर पर अध्यक्षता की।

कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों के साथ एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी ने दीप प्रज्वलित किया और बच्चों, कर्मचारियों और संकाय की उत्साही भीड़ को संबोधित किया। महानिदेशक के संबोधन के बाद, चुनिंदा स्कूलों के बच्चों को सैनिटरी नैपकिन के पैकेट वितरित करके बीडीएल-एनआईआरडीपीआर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री एस. नारायणन, महाप्रबंधक (पी एंड ए), बीडीएल ने रंगा रेडी डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना में सरकारी स्कूलों के गर्ल्स स्टूडेंट्स को 'जागरूकता सृजन एवं स्वच्छता नैपकिन की मुफ्त आपूर्ति' नामक परियोजना के बारे में श्रोताओं को संबोधित किया।

बीडीएल परियोजना को शुरू करने के बाद, मासिक धर्म स्वच्छता पर लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया । स्क्रीनिंग के बाद तीन अनुभवी पैनलिस्ट द्वारा एक विस्तृत पैनल चर्चा की गई। पैनलिस्टों ने बताया कि मासिक धर्म के स्वास्थ्य से संबंधित कमजोरियां बहुआयामी हैं और किशोर महिलाओं को एक सजातीय समूह नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि लिंग के साथ अंतर-सामाजिक पहचान हैं। उन्होंने मासिक धर्म के दौरान निपटान और स्वच्छता के आसपास अधिक से अधिक चर्चा की आवश्यकता साथ ही मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की उपलब्धता और पहुंच के साथ की ओर इशारा किया। कार्यक्रम आयोजकों को धन्यवाद और आमंत्रित बच्चों के लिए विदाई दोपहर के भोजन के साथ संपन्न हुआ।

भारत में खाद्य सुरक्षा

यह आम बात है; अन्नम् परब्रह्म स्वरूपम् ', जिसका अर्थ है भोजन ईश्वर का रूप है' 'अन्नादता सुखीभवा 'जिसका अर्थ है' भोजन दान करने वाले व्यक्ति को खुश रहने दो '। ये कहावतें हमारे दैनिक जीवन में भोजन के महत्व पर जोर देती हैं। वेदों से किसी को पता चलता है कि गुरुकुलम छोड़ने के समय, उनके शिष्यों को गुरु की बिदाई दीक्षा खाद्यान्न उगाने की थी। कौटिल्य ने अपने मैग्नम ऑपस 'अर्थशास्त्र' में सलाह दी थी कि एक राजा को अपने विषयों के दौरान उन्हें बीज और प्रावधान प्रदान करके अपना पक्ष रखना चाहिए। सूखा; प्राचीन भारत में राजा आपातकालीन भोजन स्टॉक बनाए रखते थे और लोगों को बारिश के दिन के लिए अपने स्वयं के अनाज भंडार 'रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम भूखे को दर्शन नहीं सिखा सकते हैं। वास्तव में, भोजन बुनियादी आवश्यकताओं के अनुसार मास्लो के सिद्धांत के अनुसार यह मूल शारीरिक आवश्यकता है।

आईएफपीआरआई (अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान) के महानिदेशक शेंगन फैन के अनुसार, 2030 तक भूख और कुपोषण को संबोधित किए बिना अन्य सभी सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करना व्यर्थ है। भोजन के अलावा, नागरिकों को सुरक्षित पेयजल सतत विकास के दायरे में पानी, स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सस्ती स्वास्थ्य सेवा की सुविधा होनी चाहिए।

खाद्य सुरक्षा एक ऐसी स्थिति है जब सभी लोग, हर समय, पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच रखते हैं, जो एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य वरियताओं को पूरा करता है (वर्ल्ड फूड सम्मिट, 1996)। भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत में खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए कई उपायों की शुरुआत की, जिसमें खाद्य अनाज नीति आयोग (1947) शामिल है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना के साथ-साथ 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग, एक संशोधित सार्वजनिक प्रणाली का शुभारंभ (1992), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (1997) शुरू करना और अंत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 पारित करना। हालांकि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार, लगभग 5 प्रतिशत भारतीय प्रतिदिन दो बार भोजन किए बिना बिस्तर पर चले जाते हैं। वास्तव में, ये वे लोग हैं जो वास्तव में भोजन और पोषण संबंधी असुरक्षा से पीड़ित हैं। हनुमंत राव सीएच और राधा कृष्ण (1997), ने निष्कर्ष दिया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सहित भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शीर्ष स्तर के दृष्टिकोण हैं और इसलिए सुझाव दिया गया है कि लाभार्थियों को स्थानीय पंचायतों के माध्यम से कार्यक्रमों के डिजाइन और कार्यान्वयन में भागीदार बनाने की आवश्यकता है। खेरा (2011), के अनुसार कि पीडीएस से खुले बाजार में खाद्यान्नों को भेजा गया है। बिहार में 1000 ग्रामीण परिवारों के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (ड्रेजी एट अल, 2015) के कार्यान्वयन के बाद पीडीएस के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है।

आईएफपीआरआई की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में सर्वेक्षण में शामिल 119 देशों में से भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) में 103 वां स्थान मिला। 31.1 के स्कोर के साथ, भारत भूख के स्तर से पीड़ित है जो गंभीर है (जीएचआई) स्कोर 20-34.9 को गंभीर माना जाता है; जबकि 10–19.9 का स्कोर मध्यम होता है, 10 से नीचे का स्कोर कम माना जाता है। जबकि 35-49.9 का स्कोर खतरनाक होता है, 50 और ऊपर का स्कोर बेहद खतरनाक होता है)। कुछ दक्षिण एशियाई देशों जैसे श्रीलंका (84), बांग्लादेश (88), म्यांमार (77), नेपाल (72), और चीन (29) को भारत से

सारणी 1: भारत बनिस्बत अन्य ब्रिक्स देशों में प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता

राष्ट्र	कैलोरीज् (कि.कै./दिन)	प्रोटीन (ग्राम्स दिन)	फल (कि.ग्रा./दिन)	साग-सब्जी (कि.ग्रा./वर्ष)
ब्राजिल	3,286	94.5	139.2	53.9
रशिया	3,358	101.3	68.4	109.7
भारत	**2,455**	**60.0**	**51.5**	**80.5**
चीन	12,161	407.2	347.9	666.1
दक्षिण अफ्रीका	3,007	83.5	39.1	45.3

स्त्रोत : खाद्य एवं कृषि संगठन, 2016

पाकिस्तान (106) और अफगानिस्तान (107) से बेहतर हैं । भारतीय जनसंख्या में कुपोषितों का अनुपात (14.8 प्रतिशत), पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में भोजन की बर्बादी (पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग) और पाँच वर्ष (4.3 के बीच बच्चों में शिशु मृत्यु दर) जीएचआई स्कोर की गणना करते हुए प्रतिशत) मुख्य पैरामीटर हैं । उपरोक्त आंकड़े काफी परेशान करने वाले हैं क्योंकि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश इन मानव विकास संकेतकों पर निर्भर करता है । स्वच्छता / खुले में शौच, बाल कुपोषण, विशेष रूप से स्टंटिंग का एक महत्वपूर्ण निर्धारक पाया जाता है । स्टंटिंग और भोजन बर्बाद करना एसडीजी के लिए पोषण संकेतक हैं । बच्चे विशेष रूप से पोषण संबंधी कमियों में हैं ।

खाद्य सुरक्षा के चार आयाम हैं (i) भोजन की उपलब्धता, ii) भोजन तक पहुंच, iii) भोजन का उपयोग और iv) भोजन के उत्पादन में स्थिरता। यहां, यह ध्यान रखना चाहिए कि भोजन की उपलब्धता स्वचालित रूप से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती है, जब तक कि लोगों के पास क्रय शक्ति न हो । हालांकि भोजन की पहुंच नागरिकों के आय स्तर पर निर्भर करती है, लेकिन सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास योजना, मध्याह्न भोजन योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि के कार्यान्वयन के माध्यम से अपना काम कर रही है । भोजन लोगों द्वारा तैयार किए गए भोजन की तैयारी, उपयोग और पोषण संबंधी सामग्री से संबंधित है । सरकार लोगों को सार्थक भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न और अनाज की आपूर्ति करती रही है । हरित क्रांति की बदौलत, भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में स्थिरता प्राप्त की क्योंकि 2017-18 में खाद्यान्न का उत्पादन 279.5 मिलियन टन तक पहुंच गया । भारत में प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता अन्य ब्रिक्स देशों की तालिका 1 में दर्शायी गई है ।

यह तालिका 1 से स्पष्ट है कि भारत में प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता किलो कैलोरी के साथ-साथ प्रोटीन अन्य ब्रिक्स देशों के निचले स्तर पर है । हालाँकि, दक्षिण अफ्रीका की तुलना में फलों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के मामले में भारत थोड़ा बेहतर स्थिति में है; इसी तरह, भारत सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से बेहतर है, लेकिन चीन और रूस इस मामले में हमसे आगे हैं । तो हमारा ध्यान गरीबों और भूखों को अधिक कैलोरी और प्रोटीन प्रदान करने पर होना चाहिए ताकि वे अपने भोजन और पोषण सुरक्षा को बढ़ा सकें; जैसे, लोगों को न केवल चावल और गेहूं जैसी मुख्य खाद्य वस्तुओं को शामिल करना चाहिए बल्कि कुपोषण से लड़ने के लिए दालों का सेवन करना चाहिए । यह तब हो सकता है जब हम पिरामिड आबादी के निचले हिस्से के लिए स्थायी आजीविका का निर्माण करते हैं और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाते हैं ।

विश्व बैंक के आंकड़ों (2012) के अनुसार, लगभग 27 करोड़ भारतीय कथित रूप से गरीबी रेखा से नीचे थे। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, 13.9 करोड़ गरीब लोग भारत में आजीविका की तलाश में अंतर-राज्य प्रवास का सहारा लेते हैं । इसलिए, इन लोगों के लिए भोजन की पहुंच एक प्रमुख मुद्दा है । इसके अलावा, शहरी झुग्गियों में इन विस्थापित लोगों की रहने की स्थिति बहुत ही खराब है क्योंकि उनके पास रोटी, कपडा और मकानों की कोई पहुंच नहीं है, जो मानव की मूलभूत सार्वभौमिक आवश्यकताएं हैं । मौत भूख का सबसे गंभीर परिणाम है, और बच्चे इस संदर्भ में सबसे कमजोर हैं ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार पीडीएस में दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली 'को हटाने के बारे में गंभीरता से सोच सकती है ताकि खुले बाजार में खाद्य स्टॉक के रिसाव / मोड़ को रोका जा सके; इस नीति परिवर्तन की भरपाई करने के लिए, गरीबों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है । वैकल्पिक रूप से, स्थानीय पंचायतों के माध्यम से गरीबों को खाद्य कूपन / टिकट वितरित किए जा सकते हैं । सामाजिक समारोहों में भोजन की बर्बादी एक ऐसा अपराध है जिसे जरूरतमंद अनाथों या भिखारियों को भोजन के पुनः वितरण के लिए एप्स के विकास के माध्यम से सोशल मीडिया का उपयोग करके नियंत्रित करने की आवश्यकता है । यह उल्लेख करना उचित है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, अक्षय पात्र, सेव चिल्ड्रन, अम्मा कैंटीन आदि द्वारा लॉन्च किए गए हरे कृष्ण आंदोलन देश के अन्य हिस्सों में प्रतिकृति के लिए उल्लेखनीय मॉडल हैं । भूखों को भोजन प्रदान करने की निजी पहल न केवल सरकार के प्रयासों का विकल्प होगी, बल्कि इससे गरीबों को पोषण सुरक्षा भी मिलेगी ।

दालों, दूध, फलों, सब्जियों (पत्तेदार), मांस, तेल और चीनी के उपभोग के साथ आय की स्थिति एक सकारात्मक संबंध रखती है । इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए पोषण शिक्षा की आवश्यकता है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं अपने आदतन आहार से कम से कम एक पांचवां अधिक खाएं। उदाहरण के लिए, केरल में अम्मू खाद्य पदार्थ इकाई, कुटुम्बश्री न्यूट्रीमिक्स कंसोर्टियम, आदि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्यकर और पौष्टिक भोजन की खुराक के उत्पादन में एसएचजी को संलग्न करते हैं, जिससे पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होती है ।

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम कहते हैं कि भारत स्थायी विकास हासिल करेगा जब इसके नागरिकों को भोजन और पोषण, स्वच्छ पानी और स्वच्छता, आय सृजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और क्षमता निर्माण, बिजली, दूरसंचार प्रणालियों और वित्तीय सेवाओं तक मुफ्त पहुंच होगी । भोजन के साथ-साथ पोषण सुरक्षा के माध्यम से सतत विकास को प्राप्त करने के लिए, हमें भूख को अलविदा कहने के लिए सार्वजनिक, निजी, पीपुल पार्टनरशिप मॉडल (समुदाय, निजी पार्टियों और सरकार को साझेदारों के रूप में शामिल करने) का प्रयास करना चाहिए ।

डॉ. एम. श्रीकांत
एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख
सुश्री ए. सिरीशा रेड्डी
प्रबंधक (प्रशिक्षण)
वित्तीय समावेशन एवं
उद्यमिता केंद्र
एनआईआरडीपीआर

भारत में जनसंख्या गतिशीलता और स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके निहितार्थ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र के दौरान भाषण देते हुए

स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र, मानव संसाधन विकास केन्द्र एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण समन्वय एवं नेटवर्किंग केन्द्र की मदद से मजदूरी रोजगार केन्द्र ने ''भारत में जनसंख्या गतिशीलता तथा स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उसके निहितार्थ'' पर अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) के सहयोग से 7-9 मार्च, 2019 के दौरान एनआईआरडीपीआर में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया।

सेमिनार के विषय निम्नलिखित थे:

I. विवाह, प्रजनन और परिवार नियोजन, विवाह और परिवार महिला शिक्षा, रोजगार और प्रजनन

- गर्भपात और गर्भावस्था नतीजे, परिवार नियोजन और आवश्यकता की जरूरत है

II बच्चे और किशोरों पर माता-पिता का प्रभाव

- मादक द्रव्यों के सेवन और जोखिम वाले व्यवहार
- युवा और रोजगार
- प्रजनन व्यवहार और यौन स्वास्थ्य

III पर्यावरण और जनसंख्या स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में भौगोलिक विषमताएँ

- स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय प्रभाव
- स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के साथ संबंध और जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन
- पोषण और खाद्य सुरक्षा

IV स्वास्थ्य देखभाल सिस्टम और पॉलिसी

- स्वास्थ्य देखभाल व्यय और वित्तपोषण
- स्वास्थ्य नीतियां और कार्यक्रम
- रोग और हेल्थकेयर

V ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी और पलायन

- मजदूरी रोजगार और पलायन
- प्रेषण और ग्रामीण विकास
- कृषि संकट और प्रवासन
- महिलाओं/परिवारों को पीछे छोड़ते हुए।

VI जनसंख्या अवधि

- जनसंख्या अवधि एवं स्वास्थ्य
- वृद्धायु देखभाल एवं रहन सहन व्यवस्था
- सामाजिक सुरक्षा और नीति

VII जेंडर मुद्दे

VIII डेटा और जनसांख्यिकीय पद्धति

पहले दिन के उद्घाटन सत्र में, डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, प्रो. के.एस. जेम्स और मुख्य अतिथि श्री राजेश्वर तिवारी ने दर्शकों को संबोधित किया। गणमान्य लोगों ने जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, परिवार की गतिशीलता में परिवर्तन, ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार के लिए सुधार की आवश्यकता आदि के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्ट रूप से बात की।

उद्घाटन सत्र के बाद, आईसीपीडी के 25 वर्षों पर पूर्ण सत्र: सबक सीखा और चुनौतियां आयोजित की गई। पैनल के अध्यक्ष प्रो. के. श्रीनिवासन, प्रो. लीला विसारिया, प्रो. रवि के. वर्मा और डॉ. शिरीन जीजीभोय ने विस्तार से बात की कि कैसे आईसीपीडी ने प्रजनन और बाल स्वास्थ्य मुद्दों को देखने का तरीका बदल दिया है। भारत ने आईसीपीडी के तुरंत बाद परिवार नियोजन कार्यक्रमों में लक्ष्य-निर्धारण के दृष्टिकोण को समाप्त कर दिया, लेकिन अब भी वे कार्यक्रम को संचालित करते हैं और जनसंख्या नीतियों में अभी भी प्रजनन से संबंधित लक्ष्य हैं। चर्चा के दौरान, पैनलिस्टों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या आईसीपीडी के बाद आरसीएच संबंधित कार्यक्रमों में एक अभिसरण हुआ है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या जेंडर मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाता है।

किशोरों से वयस्कता के काल में सफलता के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मुद्दा अभी भी एक बड़ी चिंता का विषय है। विपरीत मानदंड के साथ लड़कियों और लड़कों के साथ छेड़छाड़ करने वाले सामाजिक मानदंडों के बावजूद, कुछ किशोरावस्था में यौन संबंध का अनुभव होता है और प्रतिशत बढ़ रहा है। यहाँ, सवाल यह है कि क्या वे सुरक्षित सेक्स का अभ्यास करते हैं। जब तक हम एसडीजी को प्राप्त करने में विभिन्न कार्यक्रमों में तेजी नहीं लाते, तो एक बार फिर नाव को चूकने की संभावना है।

बच्चे काफी अधिक थे; एमयुएसी द्वारा किशोर लड़कियों में दुबलेपन का आकलन करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है, खासकर बीएमआई के अभाव में; बच्चों में अनाज, दूध और दूध से बने उत्पादों का सेवन न करने के लिए कम पोषण का प्रचलन अधिक है ।

अंतिम और छठा सत्र पोषण और खाद्य सुरक्षा के बारे में था । जैसे, इस सत्र में चर्चा मुख्य रूप से पोषण संबंधी मुद्दे और खाद्य सुरक्षा के इर्द-गिर्द रही। चर्चाओं को सारांशित करते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि खाद्य श्रृंखला की निरंतरता भारत में एक प्रमुख पोषण समस्या है ।

तकनीकी सत्र

संगोष्ठी के पहले दिन छह तकनीकी सत्र आयोजित किए गए और कुल 24 शोधपत्र प्रस्तुत किए गए। पेपर प्रस्तुतकर्ता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, स्नेहा, मुंबई, दिल्ली, तंजावुर, बैंगलोर, बर्दवम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली विश्वविद्यालय, श्रीनगर, मद्रास विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम, केरल विश्वविद्यालय, आईएसईसी और आईआईपीएस, मुंबई के थे ।

परिवार नियोजन पर पहले सत्र में तीन प्रतिनिधियों ने कागजात पेश किए। उन सभी ने एनएफएचएस 4 डेटा का उपयोग किया । एक कागज पर प्रकाश डाला गया कि गर्भनिरोधक का उपयोग न करने के लिए संयम और अनैतिकता सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं । तमिलनाडु में पोषण सहित मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवा को संबोधित करने वाली विभिन्न योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि एक अन्य गर्भनिरोधक उपयोग का निर्धारण करने वाले कारकों करने में गति आकलन प्रक्रिया की फिटनेस के बारे में था ।

शादी और प्रजनन क्षमता पर दूसरे सत्र में, एक पेपर में चर्चा की गई थी कि 1971 से 2016 तक आंध्र प्रदेश में प्रजनन स्तर कैसे कम हुआ है और बालिकाओं की संख्या कम करने के लिए लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है । अन्य प्रस्तुतकर्ता ने संकेत दिया कि सामाजिक समर्थन वैवाहिक सुख के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक है । तमिलनाडु और कर्नाटक में प्रजनन की गिरावट पर गर्भावस्था के चिकित्सा समापन का महत्वपूर्ण प्रभाव अच्छी तरह से उजागर किया गया था । 1990 के दशक के दौरान एक पत्र ने तमिलनाडु में 1990 से 2015 के दौरान वैवाहिक विवाह में महत्वपूर्ण गिरावट पर विस्तार से चर्चा की। कुछ मानवजनित उपायों द्वारा प्रजनन क्षमता में भेदभाव पर भी प्रकाश डाला गया ।

तीसरा सत्र मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और लैंगिक मुद्दों पर था । इस सत्र में, सीज़ेरियन सेक्शन के माध्यम से बच्चे की डिलीवरी में बढ़ती प्रवृत्ति पर विस्तार से चर्चा की गई। एक पेपर ने थ्री डिलेज मॉडल के संदर्भ में एमसीएच परिणाम के परिदृश्य पर चर्चा की, जबकि एक ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कारणों पर प्रकाश डालने की कोशिश की। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि पश्चिम बंगाल राज्य ने यौनकर्मियों के स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के दौरान तस्करी के शिकार यौनकर्मी के कल्याण और पुनर्वास के मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया ।

प्रजनन व्यवहार और यौन स्वास्थ्य पर चौथे सत्र में, यह स्पष्ट रूप से उभरा कि युवा वयस्कों में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बारे में ज्ञान और समझ बढ़ाने की आवश्यकता है; जोखिम भरे यौन व्यवहार में किशोरावस्था के भोग के सबूत हैं; भारत में युवाओं के बीच गर्भनिरोधक के उपयोग का महत्व; कैसे एक स्कूली जागरूकता कार्यक्रम तंबाकू के उपयोग के स्वास्थ्य खतरों और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की बढ़ती चुनौतियों को बढ़ाने में मदद कर सकता है ।

पांचवा सत्र बाल स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मुद्दों से संबंधित स्वाभिमान परियोजना है । इस सत्र में कुल छह पेपर प्रस्तुत किए गए थे। चर्चा के दौरान, यह बहुत स्पष्ट हो गया कि गुजरात में पारंपरिक बीहड़ प्रथाओं में सुधार की आवश्यकता है; गुजरात की महिलाएं महाराष्ट्र की महिलाओं की तुलना में अधिक लगातार और विविध खाद्य पदार्थों का सेवन करती हैं; बच्चों की बर्बादी की व्यापकता में एक अच्छी तरह से परिभाषित मौसमी बदलाव है; गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में खाद्य असुरक्षित परिवारों में कुपोषित स्थिति वाली महिलाएं और

सेमिनार के दूसरे दिन की शुरुआत द्वितीय अधिवेशन सत्र के साथ हुई थी, जिसका विषय एनएफएचएस - 4 निष्कर्षों का नीति निहितार्थ' था, इस सेशन की अध्यक्षता आईआईपीएस मुंबई के निदेशक डॉ. के.एस. जेम्स ने की थी और पैनल में जैसे स्टालवार्ट्स शामिल थे डॉ. बी. पासवान, डॉ. एस.के. सिंह, डॉ. एच. लुंडगिम, डॉ. एल.के. द्विवेदी और डॉ. पडगांवकर इत्यादि विचार-विमर्श में परिवार नियोजन, पोषण, बाल स्वास्थ्य, मृत्यु दर और प्रजनन और एनसीडी से लेकर आयामों का एक विशाल सरगम शामिल था । पैनल ने महत्वपूर्ण मुद्दों और आगे के तरीकों पर प्रकाश डाला ।

दिन के शेष समय में नौ तकनीकी सत्र देखे गए

तकनीकी सत्र 7 में ' मजदूरी रोजगार एवं ग्रामीण विकास विषय पर प्रस्तुत किया गया' जहां छह पेपर जो मुख्य रूप से भारत में कुपोषण पर अंकुश लगाने के उपायों, आईसीटी हस्तक्षेपों, पोषण अभियान, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार, एमजीएनआरईजीएस के तहत आजीविका और कमजोर वर्गों के आजीविका विश्लेषण से संबंधित एमजीएनआरईजीएस के तहत अलग-अलग समर्थ विषयों में प्रस्तुत किए गए थे।

विषय को साथ जारी रखते हुए, रोजगार और आजीविका 'विषय पर तकनीकी सत्र 8 में रोजगार और आजीविका के मुद्दों, मॉडल गांवों, आजीविका के अवसरों, पोषण की परिभाषा और मनरेगा के तहत प्रवास के मुद्दों पर चर्चा करने वाली तीन पेपर प्रस्तुतियाँ थीं।

तकनीकी सत्र 9 विषय जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर था । 'इसमें सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता से संबंधित मुद्दों से निपटने के कागजात, तेजी से शहरीकरण के प्रभाव और भारतीय

जनसांख्यिकी और स्थानिक भिन्नता पर स्वास्थ्य सर्वेक्षण से प्रमाणित है।

10 वें तकनीकी सत्र में स्वास्थ्य देखभाल 'विषय पर चार पेपर प्रस्तुत किए गए और इसमें आईएफए और एंटी-नैटल देखभाल, आयुष और बच्चों के पोषण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

जबकि 10 वां तकनीकी सत्र मुख्य रूप से बच्चों की स्वास्थ्य सेवा से संबंधित था, 11 वें तकनीकी सत्र में 'वयस्क स्वास्थ्य' पर विचार-विमर्श किया गया था। प्रस्तुतकर्ताओं ने संचयी जीवन तालिका अनुपात, वयस्क मृत्यु दर में लैंगिक असमानता, एनसीडी, डेंगू, मधुमेह मेलेटस और तपेदिक से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की । माइग्रेशन 'पर केंद्रित 12 वें तकनीकी सत्र में विचार-विमर्श नीतिगत दृष्टिकोण, आंतरिक-राज्य और संकट प्रवास और उसी के निर्धारण वाले कारकों के इर्द-गिर्द था।

मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की स्थिति, रुग्णता और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों पर प्रस्तुत पत्रों के साथ 13 वां तकनीकी सत्र जनसंख्या उम्र बढ़ने और स्वास्थ्य' से संबंधित था।

14 वां तकनीकी सत्र बुजुर्ग देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल व्यय 'पर पिछले सत्र के अनुरूप था। प्रस्तुतकर्ताओं ने स्वास्थ्य देखभाल व्यय, क्षेत्रीय विविधताओं, मुकाबला रणनीतियों और राज्य के हस्तक्षेप से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। दिन का आखिरी सत्र स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रमों पर था। प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य व्यय और आय, एचआईवी / एड्स और एसटीडी, स्वास्थ्य सेवा सेवाओं के उपयोग और स्वास्थ्य बीमा पर चर्चा की। आयोजन समिति में आईआईपीएस, मुंबई संरक्षक: प्रो. के.एस. जेम्स, निदेशक और सीनियर प्रोफेसर, प्रो. एच. लुंगडिम, डॉ. धनंजय, डॉ. डब्ल्यु बंसोड़, डॉ. प्रालिप के. नारज़री, डॉ. प्रीति ढिल्लों, सेमिनार सचिव, डॉ. पी. मुरुगेसन, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद मुख्य संरक्षक: डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी (आईएएस), महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, संरक्षक: प्रो. ज्योतिषी सत्यपालन, प्रमुख, सीडब्ल्यूई, डॉ. दिगंबर चिमनकर, डॉ. पी. अनुराधा, डॉ. लखन सिंह, डॉ. राजेश सिन्हा और डॉ. आकांक्षा शुक्ला, डॉ. सोनल मोबार रॉय शामिल थे।

वन संसाधन प्रबंध के लिए मुक्त स्रोत जीआईएस उपकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

श्री एच.के. सोलंकी, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर, सीगार्ड (बाएं से 14 वें) अन्य प्रतिभागियों के साथ

वन विभाग प्रबंधन, राजस्थान सरकार के सहयोग से 28 जनवरी से 1 फरवरी, 2019 के दौरान 'ओपन सोर्स जीआईएस टूल्स के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था । बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च (बीआईएसआर), जयपुर ने अनुरोध पर कार्यक्रम में सहयोग किया। वन विभाग, राजस्थान सरकार और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज (एनआईआरडीपीआर) ने संकाय / संसाधन व्यक्तियों के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2016 बैच के चार भारतीय वन सेवा (आइएफएस) अधिकारियों और आईटी कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों के साथ 12 राजस्थान वन सेवा (आरएफएस) अधिकारियों सहित कुल 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आयोजन में विभिन्न कैडर और आईटी विशेषज्ञों के वन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र में डॉ. एन. सी. जैन, आईएफएस, पीसीसीएफ, डब्ल्यूएफ & पीएस श्री के.सी. मीणा, आईएफएस, पीसीसीएफ, वाइल्ड लाइफ; श्रीमती शैलजा देवल, आईएफएस, सीएफ, वाइल्ड लाइफ, वन विभाग ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में दौरान प्रतिभागी

कार्यक्रम के दौरान, प्रौद्योगिकी के लिए एक परिचय दिया गया था और संभावित अनुप्रयोगों पर चर्चा की गई थी। इसके अलावा, कुछ मुक्त और खुले स्रोत उपकरण प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त अनुभव के साथ पेश किए गए थे।

उपकरण निम्न रूप में इस प्रकार हैं:

- ओएसएमएएनडी (एंड्रॉइड और आईओएसबेड मोबाइल मैपिंग एप्लिकेशन) - यदि 5-10 घंटों के बीच सटीकता की आवश्यकता होती है तो हैंडहेल्ड जीपीएस का उपयोग करने की आवश्यकता को हटा देता है।
- ओपन डाटा किट (ओडीके) - मल्टीपल में मल्टीएजोग्राफिक, मल्टी-फीचर की जानकारी इकट्ठा करने और एकत्र करने के लिए एंड्रॉइड आधारित टूल
- डेटा निर्माण, समेकन और विश्लेषण मंच के रूप में क्यूजीआईएस

प्रशिक्षण के दौरान, बीआईएसआर, जयपुर के रिमोट सेंसिंग के प्रमुख डॉ. महावीर पुनिया ने रिमोट सेंसिंग की अवधारणा और अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा की। डॉ. एन.सी. जैन, पीसीसीएफ, डब्ल्यूपी एंड एफएस, वन विभाग, राजस्थान सरकार ने ओडीके सत्रों के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने संसाधन व्यक्तियों और प्रतिभागियों के साथ विस्तृत चर्चा की। डॉ. एन. सी. जैन के निर्देशों और सलाह के आधार पर वन विभाग के आईटी और जीआईएस विभाग के कर्मचारी भी कार्यक्रम के संबंधित सत्रों में शामिल हुए।
श्री नरेंद्र सिंह, ओडीके विशेषज्ञ और डेटा प्रबंधक, भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (आईआईएचएमआर), जयपुर ने ओडीके अनुप्रयोगों और सर्वर कंप्यूटर की स्थापना पर सत्र लिया। बाकी सत्र श्री एच.के. सोलंकी द्वारा संचालित किए गए।

तीसरे दिन, वन पॉइंट एसेट्स और पटरियों के मोबाइल-आधारित डेटा संग्रह के लिए पास के झालाना वाइल्ड लाइफ रिज़र्व में आधे दिन के क्षेत्र दौरा की व्यवस्था की गई, जिसमें मुफ्त और ओपन सोर्स और ओपन डेटा किट (ओडीके) मोबाइल मैपिंग एप्लिकेशन का उपयोग किया गया। बिंदु परिसंपत्तियों के संग्रह के अलावा, सभी प्रतिभागियों ने ऑफ़लाइन मोड में अपने मोबाइल द्वारा एक ही ट्रैक के बीच में कम से कम एक ट्रैक डेटा एकत्र किया।

मोबाइल आधारित डेटा संग्रह के अलावा, वन्यजीव निगरानी और राजस्थान की एंटीपॉइशिंग प्रणाली, मुख्य रूप से राजस्थान के पांच प्रमुख वन्यजीव भंडार से डिज़ाइन की गई थी।

बाद में, डेस्कटॉप क्यूजीआईएस सॉफ्टवेयर और डेटा आयात, कल्पना और विश्लेषण किया गया। यह पाया गया कि सभी ट्रैक चौड़ाई सीमा के 8-10 मीटर के दायरे में रहे है। इसलिए, यह पूरी तरह से निष्कर्ष निकाला गया था कि मोबाइल ऐप की मदद से और मानक मोबाइल का उपयोग करके, फ़ील्ड डेटा को पांच मीटर त्रुटि के साथ, इसी तरह के इलाके की स्थिति में एकत्र किया जा सकता है। एकत्र किए गए डेटा को जीआईएस वातावरण में डाउनलोड और कल्पना की गई थी।

ओडीके का उपयोग करते हुए वन विभाग में वास्तविक डेटा संग्रह के लिए, संसाधन व्यक्ति द्वारा ओडीके कुल के लिए एक सर्वर कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर किया गया था।

इसके अलावा, श्री नरेंद्र सिंह को एक केंद्रीय डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, विश्लेषण और मानचित्र संरचना मंच के रूप में ओपन सोर्स क्यूजीआईएस सॉफ्टवेयर पर पर्याप्त ज्ञान और अनुभव सत्र संचालित किए।

पाठ्यक्रम सामग्री और प्रशिक्षण के बाद समर्थन

पाठ्यक्रम सामग्री गूगल ड्राइव साझाकरण के माध्यम से प्रदान की गई थी यू ट्यूब चैनल की सदस्यता (जीआईएस संबंधित सामग्री के लिए समर्पित)। प्रशिक्षण के बाद के समर्थन के लिए, पिछले प्रशिक्षण में राजस्थान सरकार के वन विभाग के लिए बनाए गए एक समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप में सभी प्रतिभागियों द्वारा सदस्यता ली गई थी। इसके अलावा, प्रतिभागियों को एक समर्पित लिंक्डइन समूह में शामिल होने की सलाह दी गई जिसका प्रबंधन पाठ्यक्रम निदेशक श्री एच.के. सोलंकी द्वारा किया जा रहा है। अपने जीआईएस प्रशिक्षण प्रतिभागियों के लिए। मुक्त टीम व्यूअर रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाइव समर्थन की संभावना का भी वर्णन किया गया और प्रदर्शित किया गया।

मान्यता और प्रतिक्रिया

मान्यता सत्र में, डॉ. जी.वी. रेड्डी, आईएफएस, पीसीसीएफ; डॉ. एन.सी. जैन, आईएफएस, पीसीसीएफ; तथा

श्री अनुराग भारद्वाज, आईएफएस, अपर पीसीसीएफ, आईटी, वन विभाग ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और उनकी प्रतिक्रिया ली। मूल्यांकन के दौरान, अधिकारियों और प्रतिभागियों के तैयार संदर्भ के लिए पाठ्यक्रम निदेशक द्वारा प्रशिक्षण सारांश प्रस्तुत किया गया था।

समन्वयक

श्री एच.के. सोलंकी, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर, सीगार्ड ने पाठ्यक्रम का समन्वय किया। डॉ. जी. वी. रेड्डी, आइएफएस और पीसीसीएफ, प्रशिक्षण, अनुसंधान, विस्तार और मूल्यांकन (ट्री) ने वन विभाग, राजस्थान सरकार के कार्यक्रम का समन्वय किया। रिमोट सेंसिंग डिवीजन, बीआईएसआर जयपुर के प्रमुख डॉ. महावीर पुनिया ने बीआईएसआर से कार्यक्रम का समन्वय किया।

पीएमएजीवाई के तहत ग्राम विकास योजना की तैयारी पर क्षेत्रीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण और एसआईपीआरडी, गुवाहाटी, असम में जीपीडीपी के साथ एकीकरण

डॉ. टी. विजय कुमार, अध्यक्ष, सीईएसडी (पहली पंक्ति में बाई ओर से तीसरे, श्री दीपक शाह, अवर सचिव, एमओएसजे एवं ई, भारत सरकार (पहली पंक्ति, बांई ओर से चौथै) और डॉ. सत्य रंजन महाकुल, सहायक प्रोफेसर, सीईएसडी (पहली पंक्ति में बाई ओर से पहले) , कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्य प्रतिभागियों के साथ)

1-2 मार्च, 2019 के दौरान राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान, गुवाहाटी, असम में जीपीआईआर के तहत ग्राम विकास योजना की तैयारी पर एनआईआरडीपीआर ने ईक्विटी और सामाजिक विकास केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण का आयोजन किया । इस कार्यशाला में असम और त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 48 अधिकारियों ने भाग लिया ।

कार्यशाला का उद्घाटन 1 मार्च, 2019 को श्री सुरजीत बोरगोहिन, एसआईपीआरडी, असम के उप निदेशक प्रशिक्षण द्वारा स्वागत नोट के साथ उद्घाटन भाषण किया गया । पीएमएजीवाई के तहत ग्राम विकास योजना के महत्व पर ध्यान दिया गया था । अरविंद कुमार, निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, एमओएसजे एवं ई, भारत सरकार उन्होंने विभिन्न सामाजिक आर्थिक निगरानी संकेतकों और पीएमएजीवाई के दिशानिर्देशों पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने निगरानी समितियों और उनकी संरचना को गांव, राज्य, जिला और केंद्र जैसे विभिन्न स्तरों पर रखने के तौर-तरीकों पर चर्चा की। डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीईएसडी ने समिति के सदस्यों की क्षमता निर्माण और विभिन्न सर्वेक्षणों के प्रारूप, एमआईएस के उपयोग और ग्राम विकास योजना (वीडीपी) के विकास के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली पर जोर दिया ।) ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ एकीकरण। दो दिवसीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण ने पीएमएजीवाई के कार्यान्वयन के बारे में विभिन्न पहलुओं को कवर किया जिसमें सर्वेक्षण प्रारूप, संशोधित दिशानिर्देश, पीएमएवाईवाई की नई वेबसाइट का परिचय, पीएमएवाई के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली, वीडीपी की तैयारी, पीएमएजीवाई के अभिसरण पहलू, कौशल के लिए प्रस्तुतीकरण जीपीडीपी के साथ वीडीपी का एकीकरण, डेटा एंट्री पर प्रतिभागियों के लिए हस्त अनुभव, एसआईएम का उपयोग और पीएमएजीवाई के तहत मॉडल गांवों के विकास के लिए गैप फिलिंग फंड के उपयोग के लिए योजना शामिल हैं ।

कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण 2 मार्च, 2019 को डॉ. आर.एम. पंत, निदेशक, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी द्वारा समापन भाषण के साथ समाप्त हुआ। उन्होंने गांव के स्तर पर उचित योजना के माध्यम से वंचित समुदायों के विकास को रेखांकित किया, यह निर्दिष्ट करते हुए कि मॉडल गांवों के निर्माण के लिए प्रभावी टीम नेतृत्व के माध्यम के तहत जीपीडीपी के साथ एकीकरण महत्वपूर्ण है ।

कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीईएसडी, डॉ. सत्य रंजन महाकुल, सहायक प्रोफेसर, सीईएसडी, श्री सुरजीत बोरगोहिन और श्री पाबित्रा कलिता, एसआईपीआरडी, गुवाहाटी, असम के उप निदेशक द्वारा समन्वित किया गया था ।

ग्रामीण विकास के लिए भू-संसूचना अनुप्रयोग पर लाइब्रेरी टॉक

डॉ. एन.एस. आर. प्रसाद, सहायक प्रोफेसर, सीगार्ड द्वारा ग्रामीण विकास के लिए भू-संसूचना अनुप्रयोग पर लाइब्रेरी टॉक प्रस्तुत करते हुए । । श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, प्रमुख, सीडीसी भी देखे जा सकते हैं

एनआईआरडीपीआर में सेंटर फॉर डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन ने विभिन्न विषयों पर अकादमिक चर्चा और बहस आयोजित करने के लिए एक पहल के रूप में लाइब्रेरी टॉक शुरू किया, जो विभिन्न केंद्रों के संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों को लाभान्वित कर सकती है । ग्रामीण विकास के लिए भू-सूचना विज्ञान अनुप्रयोगों पर लाइब्रेरी टॉक 12 मार्च, 2019 को आयोजित की गई थी। मुख्य वक्ता डॉ. एन.एस.प्रसाद, सहायक प्रोफेसर, सी-गार्ड थे।

सीडीसी की प्रमुख डॉ. आकाँक्षा शुक्ला ने अतिथियों का परिचय दिया और एनआईआरपीआरपी के संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों सहित दर्शकों का स्वागत किया ।

जीआईएस क्या है?

एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) डेटा एकत्र करने, प्रबंधन और विश्लेषण करने के लिए एक रूपरेखा है । भूगोल के विज्ञान में निहित, जीआईएस कई प्रकार के डेटा को एकीकृत करता है । यह स्थानिक विश्लेषण करता है और नक्शे और त्री डी दृश्यों का उपयोग करके जानकारी की परतों को दृश्य में व्यवस्थित करता है । इस अनूठी क्षमता के साथ, जीआईएस डेटा में गहन अंतर्दृष्टि प्रकट करता है, जैसे पैटर्न, रिश्ते, और स्थितियां, उपयोगकर्ताओं को स्मार्ट निर्णय लेने में मदद करती हैं ।

(source: https://www.esri.com/en-us/what-is-gis/overview

डॉ. एन एस आर प्रसाद ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विषय भू-विज्ञान और इसके अनुप्रयोगों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। जीआईएस प्रशासनिक विभाजन, पानी की उपलब्धता, संसाधन मानचित्र आदि जैसे विभिन्न परतों में स्थानिक और गैर-स्थानिक डेटा दोनों को संग्रहीत करता है । यह जानकारी किसी क्षेत्र के स्थान, उसकी स्थितियों, रुझानों (कृषि, जल या आवास पैटर्न) का भी विश्लेषण करने में मदद करती है ।

उस क्षेत्र में मॉडलिंग करने में मदद करता है । जीआईएस रिमोट सेंसिंग के साथ एकीकृत है । रिमोट सेंसिंग में उपयोग किए जाने वाले सेंसर छवियों के रूप में डेटा एकत्र करते हैं, और इन छवियों का विश्लेषण और कल्पना करने के लिए विशेष क्षमताएं प्रदान करते हैं । डॉ. एन.एस.आर. प्रसाद ने रिमोट सेंसिंग के कुछ फायदों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि इसका उपयोग आगे चलकर बंजर भूमि के स्थानों को जानकर किया जा सकता है, जिसका उपयोग आय और रोजगार पैदा करने के लिए किया जा सकता है । यह वाटरशेड प्रबंधन में भी मदद करेगा।

जीआईएस का उपयोग कृषि-जलवायु योजना में किया जा सकता है, जहां इसका उपयोग मिट्टी की मैपिंग के लिए किया जा सकता है, प्रमुख फसल के प्रकार, फसल उपयुक्तता, सूखा आकलन, फसल बीमा मैपिंग, भूमि उपयोग पैटर्न, भूमि क्षरण, सिंचाई, उन्नयन, वर्षा, तापमान और उस क्षेत्र की अन्य सांस्कृतिक विशेषताओं को जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ।

जीआईएस को एमजीएनआरईजीएस जैसी सरकारी योजनाओं के साथ एकीकृत किया जा सकता है और इसका उपयोग विकास योजनाओं की निगरानी और सड़कों के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है । जीआईएस प्रशासनिक और विकास क्षेत्र में प्रभावी रूप से उपयोगी है, विशेष रूप से आपदा प्रबंधन, भूजल प्रबंधन, बाढ़ शमन, बाढ़ चेतावनी प्रणाली में। यह स्वच्छ भारत मिशन जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत परिसंपत्ति की निगरानी में भी मदद कर सकता है ।

वक्ता डॉ. एन.एस. आर. प्रसाद ने भुवन पंचायत पर विस्तार से चर्चा की । भुवन पंचायत एक वेब पोर्टल है जो क्राउड सोर्सिंग एप्रोच पर कार्य करता है । यह उस क्षेत्र पर हाई रिजोल्युशन डाटा का प्रस्ताव करता है जो मानसिक चित्रण में मदद करता है ।

श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने जीआईएस के क्षेत्र में बेहत्तर अनुसंधान के लिए सी-गार्ड के दल की प्रशंसा की और बताया की प्रशासन में प्रभावी अनुश्रवण के लिए उपयोगी है ।

कार्यक्रम के अंत में डॉ. आकाँक्षा शुक्ला ने वक्ता को धन्यवाद दिया ।

सीडीसी पहल

जेंडर एकीकरण पर संयुक्त राष्ट्र परियोजना के लिए पूर्व एनआईआरडीपीआर संकाय सदस्य को समूह प्रबंधक के रूप में चुना गया

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के एक पूर्व संकाय सदस्य, डॉ. श्रीधर सीतारमण को मुख्यधारा के विकास में जेंडर एकीकरण पर संयुक्त राष्ट्र परियोजना के लिए समूह प्रबंधक के रूप में चुना गया।

यह परियोजना कनाडा की अर्थव्यवस्था के मुख्यधारा के विकास में जेंडर एकीकरण पर है। यह 2019 के पतन से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र का कार्य है। यह प्रति वर्ष जीएस 7 (यूएस $ 450,000) का यूएन स्केल वहन करता है। कनाडा के 10 प्रांतों और 3 क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चार उम्मीदवारों का विश्व स्तर पर चयन किया गया था और डॉ. श्रीधर को ओंटारियो और न्यू ब्रंसविक के प्रांतों और नुनावुत के क्षेत्र को सौंपा गया है। वह समूह 1 के नेता होने के अलावा चार समूहों की गतिविधियों का समन्वय करेंगे।

डॉ. श्रीधर सीतारमण अगस्त 1982 में एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में शामिल हुए और सितंबर 2014 में एनआईआरडीपीआर की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए। एनआईआरडीपीआर में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने महिला सशक्तिकरण, महिला उद्यमिता, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन और नियंत्रण, जेंडर न्याय और नियंत्रण के क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित की। उसी पर किताबें लिखीं।

मई 1998 में, उन्होंने जेंडर को मुख्यधारा से जोड़ना - मंत्रालय के महिला और बाल विकास, भारत सरकार जेंडर बजट सेल के लिए वैचारिक ढांचे, कार्यप्रणाली और अच्छी प्रथाओं की प्रस्तुति के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की।

एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी में, उन्होंने एक प्रशिक्षण समन्वयक (अगस्त 2008 - जून 2012) के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने जेंडर को मुख्यधारा से जोड़ना और जेंडर बजट में विशेषज्ञता विकसित की। जेंडर बजट कंसल्टेंट के रूप में, उन्होंने नागालैंड और त्रिपुरा की सरकारों को अपने राज्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में सहायता की। यह उत्पाद नागालैंड और त्रिपुरा के लिए जेंडर बजट मैनुअल की तैयारी थी।

उन्होंने लैंगिक समानता पर एक विकास नीति पत्र भी तैयार किया और इसे सुधारने के लिए कदम उठाए - यूरोप, इंस्टीट्यूट फॉर जेंडर इक्वेलिटी (ईआईजीई), प्राग, चेक रिपब्लिक के साथ छह महीने की अवधि के लिए ग्रीस, हंगरी और स्लोवाकिया के केस स्टडीज। महीने (जून 2016 - जनवरी 2017)। विकास नीति पर इस पत्र को ईआईजीई और संबंधित देशों द्वारा स्वीकार किया गया था। संयोग से, इन तीन देशों में यूरोपीय संघ में लैंगिक समानता की दर सबसे कम है। ग्रीस, हंगरी और स्लोवाकिया में जेंडर समानता का कवरेज यूरोपीय संघ के औसत 66.2 प्रतिशत के मुकाबले 50.00, 50.80 और 52.40 प्रतिशत है। वह उन सदस्यों में से एक थे, जिन्होंने नीति चक्र के प्रत्येक चरण में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए यूरोपीय संघ संस्थानों और सरकारी निकायों की सहायता के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका विकसित की।

इसका परिणाम था जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना : हेल्प टू ए मोर इक्विटेबल सोसाइटी, जिसने 15 तरीकों और औजारों की पहचान की, जो यह बताता है कि कैसे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नीतियों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के माध्यम से जेंडर को एकीकृत किया जाए।

जेंडर न्याय पर उनके ग्रंथ को बहुत सराहा गया और परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ की जलवायु परिवर्तन नीति में जेंडर न्याय को मुख्य धारा से जोड़ना' पर एक पत्र की प्रस्तुति और इसके माध्यम से जेंडर न्याय और कार्यशाला में संघ के प्रवास और विकास नीति के साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज, डबलिन, आयरलैंड गणराज्य (29 और 30 नवंबर, 2018) में यूरोपीय संघ की बाहरी नीतियां के साथ समन्वय किया गया।

डॉ. श्रीधर ने संपूर्ण गुणवत्ता पर प्रबंधन, जेंडर बजटिंग और ऑडिटिंग, जेंडर जस्टिस और महिला सशक्तीकरण और इन विषयों पर संबंधित सत्र भारतीय प्रशासनिक कॉलेज, हैदराबाद, तेलंगाना में; जवाहरलाल नेहरू वास्तुकला और ललित कला विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना; केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान, त्रिचुर, केरल; राजकोषीय नीति संस्थान, बेंगलुरु, कर्नाटक में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। वह यूनाइटेड थियोलॉजिकल कॉलेज, बेंगलुरु, कर्नाटक के एक प्रोफेसर हैं, जहां वे महिला अध्ययन पर डिप्लोमा छात्रों के लिए सत्र लेते हैं और सेरामपुर विश्वविद्यालय, सेरामपुर, हुगली जिले, पश्चिम बंगाल में डिग्री छात्रों के लिए महिला अध्ययन को संचालित करते हैं। वह बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अवार्ड, 2014 और चैंपियन ऑफ चिल्ड्रन अवार्ड, 2014 के प्राप्तिकर्ता हैं।

डॉ. श्रीधर सीतारमण वर्तमान में 2015 से अरुपा मिशन रिसर्च फाउंडेशन, भुवनेश्वर, ओडिशा के सलाहकार (जेंडर और ग्रामीण विकास) हैं।

इसके अलावा, डॉ. श्रीधर के पास कनाडा के मुख्यधारा विकास 'में जेंडर इंटीग्रेशन' मान्यता है और उन्होंने चार समूहों के लिए समग्र समूह के नेता के अलावा ओंटारियो और न्यू ब्रंसविक और टेरिटरी ऑफ नुनावुत के प्रांतों को ग्रुप लीडर के रूप में सौंपा।

पीएमएजीवाई के तहत ग्राम विकास योजना की तैयारी पर क्षेत्रीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण और मैसूरु में जीपीडीपी के साथ एकीकरण

कार्यशाला- प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सीईएसडी के प्रमुख डॉ. टी. विजय कुमार

समानता और सामाजिक विकास केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने अब्दुल नजीर साब राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (एएनएसएसआईआरडीपीआर), मैसूरु, कर्नाटक में जीपीडीपी के साथ पीएमएजीवाई के तहत ग्राम विकास योजना की तैयारी पर दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण का आयोजन किया। 5-6 मार्च, 2019 के दौरान इस कार्यशाला में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 60 अधिकारियों ने भाग लिया और पीएमएजीवाई के नियोजन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

कार्यशाला का उद्घाटन 5 मार्च, 2019 को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक, श्री अरविंद कुमार द्वारा एक स्वागत नोट के साथ किया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संशोधित दिशा-निर्देशों पर जोर दिया और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक निगरानी योग्य संकेतकों को समझाया। इसके अलावा, उन्होंने निगरानी समितियों के गठन और ग्राम, राज्य, जिला और केंद्र जैसे विभिन्न स्तरों पर समितियों की रचना के तौर-तरीकों पर चर्चा की। डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीईएसडी, ने ग्राम विकास योजना के महत्व पर चर्चा करते हुए, समिति के सदस्यों की क्षमता निर्माण और विभिन्न सर्वेक्षण प्रारूपों, एमआईएस के उपयोग और कार्यप्रणाली को अपनाने के लिए पदाधिकारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। ग्राम विकास योजना (वीडीपी) के विकास के लिए, और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ एकीकरण पर दो दिवसीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण ने पीएमएजीवाई के कार्यान्वयन के बारे में विभिन्न पहलुओं को कवर किया जिसमें सर्वेक्षण प्रारूप, संशोधित दिशानिर्देश, पीएमएवाईवाई की नई वेबसाइट का परिचय, पीएमएजीवाई के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली, वीडीपी की तैयारी, पीएमएजीवाई के अभिसरण पहलुओं, कौशल शामिल हैं। जीपीडीपी के साथ वीडीपी के एकीकरण के लिए, शिक्षा के सांप्रदायिकता पर नागालैंड का केस स्टडी, डेटा एंट्री पर प्रतिभागियों के लिए अनुभव, एमआईएस का उपयोग और पीएमएजीवाई के तहत मॉडल गांवों के विकास के लिए अंतर भरने के लिए धन का उपयोग करने की योजना है।

कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण 6 मार्च, 2019 को एएनएस एसआईआरडीपीआर, मैसूरु के उप निदेशक के समापन भाषण के साथ संपन्न हुआ। अपने भाषण में, उन्होंने पीएमएजीवाई के तहत ग्रामीण स्तर पर उचित योजना के माध्यम से सीमान्तीकृत समुदायों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। कार्यशाला सह प्रशिक्षण डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीईएसडी डॉ. रुबीना नुसरत, सहायक प्रोफेसर, सीईएसडी और श्री अबू बकर, एएनएसएसआईआरडीपीआर, मैसूरु, कर्नाटक के संकाय द्वारा समन्वित किया गया था।

भारत सरकार सेवार्थ

बुक पोस्ट
(मुद्रित सामग्री)

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030
टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
संपादक : डॉ. के पापम्मा
सहायक संपादक: कृष्णा राज
के.एस. विक्ट र पॉल

एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से
डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी, श्री अशफाख हुसैन